

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

विषय— महानिदेशालय के द्वितीय तल पर एन0एच0एम0 कार्यालय के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या—NHMWing/Construction/B.4.1.5.4.5/2015-16/1812, दिनांक 26.03.2016 एवं पत्र संख्या—NHMWing/Construction/B.4.1.5.4.5/2015-16/7943, दिनांक 15.11.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या—857/XXVIII-4-2016-67(5)/2014टी0सी0, दिनांक 30.09.2016 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में रू0 57.88 करोड़ की धनराशि एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों द्वारा धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी है।

भारत सरकार द्वारा एन0एच0एम0 सप्लीमेंट्री आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2015-16 के एफ0एम0आर0 Code-B4.1.5.4.5 में धनराशि रू0 88.78 लाख (रू0 अठठासी लाख अठहत्तर हजार मात्र) तथा आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2016-17 के एफ0एम0आर0 Code-B4.1.5.4.5 में धनराशि रू0 314.72 (रूपये तीन करोड़ चौदह लाख बहत्तर हजार मात्र) का इस प्रकार कुल रू0 403.50 लाख (रूपये चार करोड़ तीन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3— उक्त के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति की दिनांक 28.10.2016 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय संबंधी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या—1552/186-व्य0वि0स0/रा0यो0आ0/2016-2017, दिनांक 08.11.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा चिकित्सा-स्वास्थ्य महानिदेशालय के द्वितीय तल पर एन0एच0एम0 कार्यालय के निर्माण हेतु (सिविल कार्यों हेतु रू0 301.80 लाख एवं अधिप्राप्ति कार्यों हेतु रू0 342.53 लाख) परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 644.33 लाख (रू0 छः करोड़ चवालिस लाख तैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4— अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में व्यय वित्त समिति की बैठक के संबंध में नियोजन विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 08.11.2016 के क्रम में चिकित्सा-स्वास्थ्य महानिदेशालय के द्वितीय तल पर एन0एच0एम0 कार्यालय के निर्माण हेतु उक्त कार्य हेतु औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 644.33 लाख (रू0 छः करोड़ चवालिस लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रू0 403.50 लाख (रूपये चार करोड़ तीन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि

निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आहरित कर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त सम्बन्धित कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात् कोई भी आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
4. वर्तमान परिदृश्यों में Energy efficient building का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भवनों को विश्व स्तर के मानकों के अनुसार Energy efficient बनाए जाने तथा इस हेतु building के सम्बन्ध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाय तथा इस सम्बन्ध में Tata Energy research institute (TERI) द्वारा जारी गाईड लाईन/Representative Designs of Energy का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. सौर उर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाय, यथा सोलर गीजर, सोलर कुकर आदि।
6. निर्माण सामग्री यथा ब्रिक्स, सीमेन्ट, स्टील एवं अन्य का Frequency के अनुरूप NADL Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।
7. कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का Structural Design सक्षम स्तर से वेट कराकर एक प्रति राज्य योजना आयोग को भी उपलब्ध करायेंगे साथ ही रेन फोर्समेन्ट स्टील की मात्रा Bar bending schedule के आधार पर आंकलित किया जाय तथा बचत के सम्बन्ध में प्र०वि० तथा राज्य योजना आयोग को अवगत कराया जायेगा।
8. Electrical Items जैसे switches, wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath fittings, Geyser, water tank, pipes आदि Toilet Items, wood items आदि की Market Survey कर डी०एस०आर० दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्व में ही कम से कम 3 निर्माता या उनके authorised/distributor के Quotations प्राप्त कर Brand Name निर्धारित कर लिया जाय। यदि प्रोक्योरमेन्ट मर्दों की लागत रू० 3.00 लाख से अधिक हो तो कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (यथा संशोधित, 2015) के अनुसार कर लिया जाय।
9. आगणन में कार्यदायी संस्था में डी०एस०आर० की दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मर्दें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता की दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मर्दों का आगणन में समायोजन करेंगे, जो अपरिहार्य मर्दें हैं। मर्दें डी०एस०आर० में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मर्दों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।
10. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
11. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
12. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
14. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
15. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक करते हुये वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र महानिदेशालय एवं शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
16. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरंतर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराते हुए भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्ययक वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 2210-03-110-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें-0104-एन0एच0एम0(एन0आर0एच0एम0 सहित) के नामे डाला जायेगा। यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या-171(P)/XXVII(3)/2016-17, दिनांक 02 नवम्बर, 2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-953 (1)/XXVIII-4-2016-70/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. प्रमुख सचिव-मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. वित्त नियंत्रक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून।
12. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन विभाग/चिकित्सा अनुभाग-5/एन0आई0 सी0।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से



(शिवेन्द्र नारायण सिंह)

अनु सचिव।